The House met at eleven of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair

--

PAPERS LAID ON TABLE

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I lay on the Table, under sub-section (1) of Section 28 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Mines Notification No. G.S.R. 1120 (E), dated the 8th December, 2016, publishing the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession (Amendment) Rules, 2016.

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (i) (a) Annual Report and Accounts of the Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF), New Delhi, for the year 2015-16, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Foundation.
 - (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (i) (a) above.
- (ii) (a) Annual Report of the National Institute of Rural Development and Panchayati Raj (NIRD& PR), Hyderabad, for the year 2015-16.

- (b) Annual Accounts of the National Institute of Rural Development and Panchayati Raj (NIRD& PR), Hyderabad, for the year 2015-16, and the Audit Report thereon.
- (c) Review by Government on the working of the above Institute.
- (d) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (ii) (a) above.

SHRI RADHAKRISHNAN P.: Sir, I lay on the Table, under sub-section (4) of Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Road Transport and Highways Notification No. S.O. 2590 (E), dated the 8th October, 2014, amending Notification No. S.O. 1365 (E), dated the 13th December, 2004, to insert certain entries in the original Notification, along with Explanatory Memorandum and delay statement.

SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA: Sir, I lay on the Table—

- I. (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (2) of Section 103 and Section 106 of the Major Port Trusts Act, 1963:—
 - (a) Administrative Report of the Kolkata Port Trust, Kolkata, for the year 2015-16.
 - (b) Annual Accounts of the Kolkata Port Trust, Kolkata, for the year 2015-16, and the Audit Report thereon.
 - (c) Review by Government on the working of the above Port Trust.
 - (d) Review by Government of the Annual Accounts of the

above Port Trust.

- (2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.
- II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under Section 5(E) of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948:—
 - (a) Annual Administration Report and Accounts of the Calcutta Dock Labour Board (CDLB), Kolkata, for the year 2015-16, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Board.

(Ends)

MATTERS RAISED WITH PERMISSION OF CHAIR

ALLEGED BAN ON DEMOCRATIC RIGHTS OF STUDENTS IN SOME CENTRAL UNIVERSITIES

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार): महोदय, तकरीबन एक साल पहले बीएचयू में छात्रों ने साइबर लाइब्रेरी को रात भर खोलने की मांग की। उनके prospectus में यह बात है कि साइबर लाइब्रेरी रात में भी खुलेगी और इसके लिए उन्होंने मांग की। वहां के वीसी ने रात में साइबर लाइब्रेरी खोलने से मना किया। उसके बाद लड़के धरने पर बैठे। इस घटना को घटे एक साल हो गया, लेकिन इसके लिए उन लड़कों को प्रताड़ित किया जा रहा है। नौ लड़कों को कॉलेज से निकाल दिया गया। इधर कुछ महीने पहले दो गुटों में

झगड़ा हुआ, उसमें इन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। इन लोगों को examination देने से रोका जा रहा है और इनके गार्जियन्स को फोन करके यूनिवर्सिटी की तरफ से धमिकयां दी जा रही हैं।

महोदय, वहां पर लड़कियों के साथ क्या हो रहा है? वहां पर लड़कियों को हॉस्टल में नॉन-वैज खाने की मनाही है। लड़के नॉन-वैज तो खा सकते हैं, लेकिन लड़िकयां नॉन-वैज नहीं खा सकती हैं। लड़िकयां आठ बजे के बाद होस्टल में नहीं आ सकती हैं, नौ बजे के बाद वे सैल फोन पर बात नहीं कर सकती हैं। वहां पर लडिकयों को होस्टल में इंटरनेट की सुविधा नहीं है। लड़कों को यह सुविधा मिलती है, लेकिन लड़कियों को यह सुविधा नहीं मिलती है। लड़कों को यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है, लेकिन लड़कियों को यह सुविधा नहीं है। इस तरह से ट्रंप के टाइप का फरमान वहां के वीसी जारी कर रहे हैं। इसके लिए वहां पर लडके और लडकियां आंदोलन कर रहे हैं। वहां पर एडिमशन के समय ही लडिकयों से इस तरह का affidavit लिया जा रहा है कि वे किसी भी आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगी। चूंकि उनको एडिमशन कराना है, इसलिए उनका इस तरह से लिखना मजबूरी हो जाता है। इस तरह की ज्यादती वहां चल रही है। जिन नौ छात्रों को निकाला गया है, उनमें से ज्यादातर ओबीसी के हैं, दलित हैं, माइनॉरिटी के हैं। इस तरह से उनकी लाइफ बरबाद हो रही है।

सर, इसी तरह की स्थिति जेएनयू में है। आप जानते हैं कि अभी जेएनयू में 15 लड़कों को सस्पेंड किया गया है। उनको अभी हाल में अंतरिम रिजस्ट्रेशन का मौका तो मिला है, लेकिन वे लोग भूख हड़ताल पर बैठे, उन्होंने अपनी डिग्रियां जलाने की कोशिश की और हद तो यह हो गई कि वहां पर एनएसयूआई, एबीवीपी भी धरने पर बैठे कि वहां के वीसी ज्यादती कर रहे हैं। पहले तो एबीवीपी को छोड़ कर अन्य छात्र संगठन आंदोलन करते थे, लेकिन अब एबीवीपी के लोग भी वहां के वीसी से आजिज़ आ गए हैं। महोदय, मामला क्या है? मामला यह है कि यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि पीएचडी में एडिमशन के लिए अब 100 परसेंट इंटरव्यू होगा, जब कि लड़के कह रहे हैं कि यह 10 परसेंट होना चाहिए। वे इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि क्योंकि जो रिटन में भी टॉप में आ जाते हैं....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Time is over. It is not going on record.

श्री अली अनवर अंसारी : *

श्री उपसभापति : आप अपनी बात बोल चुके हैं, कृपया आप बैठ जाइए। अब आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है, इसलिए कृपया आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... It is not going on record.

श्री अली अनवर अंसारी : *

* Not recorded.

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश) : महोदय, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करते हुए कहना चाहती हूँ कि ...(व्यवधान)...

श्री तपन कुमार सेन : महोदय, सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी में यह क्या हो रहा है? ...(व्यवधान)...

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार) : महोदय, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

SHRI MAJEED MEMON (MAHARASHTRA): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI C.P. NARAYANAN (KERALA): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

(1b/केएलएस-एनकेआर पर आगे)

NKR-KLS/1B/11.05

श्रीमती विप्लव टाकुर: लड़िकयों के साथ ऐसा व्यवहार होना, इन लोगों की मैंटेलिटी बताता है।..(व्यवधान)..

SHRI TAPAN KUMAR SEN: What is going on in the country? Are we in a democratic, socialist, secular country or are we somewhere else? ...(Interruptions)... Why is this nasty experiment being made in the Central Universities where the Central Government is ultimately the deciding authority?

SHRI D. RAJA: Let the Minister respond. ...(Interruptions)...

श्री शरद यादव: सारी सैंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कभी पिछले 70 वर्षों में इस तरह के हालात नहीं बने। आज इस यूनिवर्सिटी में या कल दूसरी यूनिवर्सिटी में, तमाम तरह की जो दिक्कतें आ रही हैं, सरकार को इस पर गम्भीर होना चाहिए। ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ आपके अंडर हैं। उनमें इस तरह की घटनाएं पहले कभी नहीं होती थीं। अब क्यों हो रही हैं? क्यों रोज नियम बदलने से किसी न किसी तरह की बच्चों को परेशानी हो रही है? यह बहुत ही गम्भीर मामला है। ..(व्यवधान)..मैं इसमें विस्तार से नहीं बोलना चाहता

लेकिन मामला बहुत गम्भीर है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आपके विश्वविद्यालय हैं, आपके हाथ में दिए गए हैं।..(व्यवधान)..

श्रीमती विप्लव टाकुर: सर,यह गम्भीर मामला है और इन लोगों की मैंटेलिटी बताता है। हमें भी बोलने का मौका दीजिए।..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : आपका कोई नोटिस इस मामले में नहीं मिला है।

श्रीमती विप्लव टाकुर: नोटिस नहीं दिया तो क्या, यह मामला गम्भीर है और इनकी मैंटेलिटी बताता है।..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : यदि आप एसोसिएट करना चाहती हैं, तो ऐसा बोलिए कि एसोसिएट करना है।..(व्यवधान)..

श्रीमती विप्लव टाकुर: महोदय, मैं इस विषय के साथ एसोसिएट करती हूं। ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : ठीक है।..(व्यवधान)..

श्रीमती जया बच्चन : *

श्रीमती विप्लव ठाकुर:*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Jayaji, this you usually do. You are not chairing, I am chairing. ...(Interruptions)... Sit down. ...(Interruptions)... What they have said is not going on record. ...(Interruptions)... Jayaji, this is not the first time you are doing such things, always you do like this. Don't question the Chair. ...(Interruptions)... You can give suggestion but you cannot

question the Chair. ...(Interruptions)... You are an hon. lady Member, behave properly. Sit down. ...(Interruptions)... What you have said will not go on record. ...(Interruptions)... All what you have said is expunged. ...(Interruptions)... Now you sit down. ...(Interruptions)...

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक़वी): माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया है और कई वरिष्ठ माननीय सदस्यों ने अपने आपको उसके साथ एसोसिएट किया है, यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटीज़ की autonomy और यूनिवर्सिटीज़ में जो administrative activities हैं, उनकी day-to-day जो activities हैं, सरकार उनमें कभी हस्तक्षेप नहीं करती।..(व्यवधान)..

*Not recorded

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Universities have autonomy also. ...(Interruptions).. आप सुनिए।..(व्यवधान)..

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: दूसरा विषय यह है कि जो विश्वविद्यालय हैं, उनकी अपनी गरिमा होती है। उनकी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशासनिक मापदंड होते हैं। हम सब छात्र आंदोलन से निकलकर आए हैं। हमें मालूम है कि अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो निश्चित तौर से छात्र अपनी बात उठाते हैं, अपनी बात को वहां के वाइसचांसलर से और वहां की administrative machinery से कहते हैं, लेकिन हमें इन चीजों का राजनीतिकरण यहां पर नहीं करना चाहिए। ..(व्यवधान).. अगर कोई स्पेसिफिक

घटना आपकी जानकारी में है..(व्यवधान).. आप हमें बताइए, हम संबंधित मंत्री के संज्ञान में उसे लाएंगे। इसके अलावा स्वीपिंग स्प्री ..(व्यवधान)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You listen. ...(Interruptions)... Listen please. ...(Interruptions)... Listen please. ...(Interruptions)...

श्री अली अनवर अंसारी : यह छोटी चीज़ नहीं है सर। ..(व्यवधान)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I allowed you. Please sit down. ...(Interruptions)... I have already allowed you. ...(Interruptions)... Now sit down. ...(Interruptions)...

श्री अली अनवर अंसारी :*

*Not recorded

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not going on record. Naqviji, Mr. Ansari has raised a specific issue. He mentioned the name of a University. He also mentioned about certain discriminations where girl students are discriminated against. Of course, I concede these are autonomous bodies. In spite of that if these things are there which are said to be unlawful, you can inform the HRD Minister to find out what the position is. That is all. Dr. T. Subbarami Reddy. ...(Interruptions)... All those who associate, their names will be added, including Shrimati Jaya Bachchan's name. ...(Interruptions)...

SHRI D. RAJA (TAMIL NADU): Sir, I also associate myself with this issue raised by the hon. Member.

SHRI MD. NADIMUL HAQUE (WEST BENGAL): Sir, I also associate myself with this issue raised by the hon. Member.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN (UTTAR PRADESH): Sir, I also associate myself with this issue raised by the hon. Member.

SHRI TAPAN KUMAR SEN (WEST BENGAL): Sir, I also associate myself with this issue raised by the hon. Member.

SHRI VIVEK GUPTA (WEST BENGAL): Sir, I also associate myself with this issue raised by the hon. Member.

SHRI K.K. RAGESH (KERALA): Sir, I also associate myself with this issue raised by the hon. Member.

SOME HON. MEMBERS: We also associate ourselves with this issue raised by the hon. Member.

(Followed by 1C/SSS)

SSS-DS/1C/11.10/

SHRI ANAND SHARMA (HIMACHAL PRADESH): Sir, we are grateful to the Chair that you have registered fully the importance of this issue. When the Minister of Parliamentary Affairs conveys this to the HRD Minister, it should be clearly underscored that this is not a small matter. Secondly, within the Constitutional framework the autonomy of the Central Universities must be protected. That is all what I have to say.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is correct. I appreciate that point.

Autonomy is very important. It should be protected. I agree. Dr. T.

Subbarami Reddy.

SHRI ABDUL WAHAB: If that is the case, what.....(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Wahabji, please sit down. Dr. T. Subbarami Reddy.

NEED TO FRAME NATIONAL POLICY TO PREVENT FOREST FIRES

DR. T. SUBBARAMI REDDY (ANDHRA PRADESH): Sir, protecting the forests from fire accidents across the country is the prime duty of the Government. It is very important. We have seen that 24,817 fire incidents took place in various parts of the country. Therefore, measures should be taken by the Government on top priority. In recent years, forest fires have increased across Central Indian forests and the Himalayan Pine forests. The frequency of such blazes has risen by more than 60 per cent. So, Madhya Pradesh has seen nearly ten-fold increase in forest fires. The three States of Odisha, Chhattisgarh and Madhya Pradesh contribute to a third of forest

fires. The prolonged forest fires destroyed 4,000 hectares of forest land across 13 districts of Uttarakhand itself. In Himachal Pradesh and Uttarakhand, over 17,502 acres have been damaged in the last year due to increasing number of forest fires. The Parliamentary Committee which had gone into the whole issue has observed that a large number of posts of frontline forest staff are lying vacant and the fire fighting equipment is almost nil in most of the cases. This is very important. It is surprising, actually. How has the Government not filled up the posts? Why are they not giving any equipment? How are they keeping quiet when there are fire accidents taking place throughout the country? The Committee has recommended procurement of sweeping machines to clear roadsides of Chirpine needles, while advocating large scale incentives and programmes, including the Mahatma Gandhi National Rural Guarantee Scheme, to collect dry pines for use as fuel and other incineration. Sir, it primarily focusses on the prevention and containing of fires in the Himalayan forests -- which is important -- spread across Uttarakhand, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. It also suggested framing a national policy to manage forest fires. This is important. I urge upon the concerned Minister to make a White Paper and tell us what action they are taking and how they are going to protect the forests. I urge upon the Central Government in the Ministry of Environment and Forests to frame a national policy on managing forest fires on an urgent basis to address these issues. I would also urge upon the hon. Minister to implement the recommendations of the Parliamentary Committee, in the short-term measures, to safeguard the forests for the future generation, especially in the wake of coming summer which is predicted to be hot and severe. I, once again, urge upon the Government to take measures on top priority. Thank you.

(Ends)

SHRI C. P. NARAYANAN (KERALA): Sir, I associate myself with the issue raised by Dr. T. Subbarami Reddy.

SHRI D. RAJA (TAMIL NADU): Sir, I also associate myself with the issue raised by Dr. T. Subbarami Reddy.

SHRI RIPUN BORA (ASSAM): Sir, I also associate myself with the issue raised by Dr. T. Subbarami Reddy.

(Ends)

PATHETIC CONDITION OF ENGINEERS CATEGORIZED UNDER GROUP 'C' IN RAILWAYS

श्री शरद यादव (बिहार): सर, मैं आपकी अनुमित से एक सवाल, जो बहुत वर्षों से सरकार के अधीन है, उठाना चाहता हूँ। सर, मेरे साथ के कई मित्र रेलवे में इंजीनियर बने हैं। आप यह जानकर ताज्जुब करेंगे कि रेलवे में जो इंजीनियर्स हैं, वे जब भर्ती होते

हैं, तब वे जूनियर इंजीनियर होते हैं और उनको "सी" ग्रेड मिलता है, जबिक भारत के बाकी सभी विभागों में ग्रेड "बी" मिलता है। ऐसे-ऐसे केस हैं कि एक जूनियर इंजीनियर "सी" ग्रेड में भर्ती होता है और सारी उम्र काम करने के बाद भी उसको एक भी प्रमोशन नहीं मिलती है। इस मामले के बारे में कई एमपीज़ आज से नहीं बल्कि वर्षों से लिख रहे हैं। यह जो disparity है, यह जो फर्क है, यह इतना बड़ा है कि एक आदमी को जिन्दगी भर किसी तरह की प्रमोशन नहीं मिलती। इस तरह रेलवे के जो इंजीनियर्स हैं, उनके साथ अन्याय और जुल्म हो रहा है।

(1डी/एमसीएम पर जारी)

MCM-PK/1D/11.15

श्री शरद यादव (क्रमागत): सरकार उस पर ध्यान नहीं देती, मैंने भी कई बार उसके बारे में लिखा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस दौर में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं रेल में हो रही हैं। आंध्र में होती हैं, ओडिशा में होती हैं, उत्तर प्रदेश में होती हैं, यानी जो सेफ्टी है, इस सेफ्टी में सबसे ज्यादा काम करने वाले, इसको देखने वाले कोई लोग होते हैं तो ये इंजीनियर्स होते हैं। इसलिए जो इंजीनियर्स हैं, इनकी जो मांग है वह जस्टिफाइड है, न्यायसंगत है। मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस डिस्पैरिटी को मिटाना चाहिए, इस अंतर को मिटाना चाहिए। जो इंजीनियर्स हैं बड़े पैमाने पर, पूरे जीवन भर जब वे देश के अन्य विभागों को देखते हैं तो उनके अंदर एक इनफीरियॉरिटी कॉम्पलेक्स हो जाता है, एक हीन भावना होती है। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से चाहुंगा कि इस विषय पर रेल मंत्री को जरूर जल्दी से जल्दी

कोई न कोई रास्ता निकाल करके इनके सवाल को हल करना चाहिए, यही मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार): महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री राम नाथ टाकुर (बिहार): महोदय, मैं भी इस विषय के साथ स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

SHRI T.K. RANGARAJAN (TAMIL NADU): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI K.T.S. TULSI (NOMINATED): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Partap Singh Bajwa.

(Ends)

DEMAND FOR PAYING ATTENTION TO PROBLEMS OF CENTRAL ARMED POLICE FORCES

SHRI PARTAP SINGH BAJWA (PUNJAB): Sir, I rise to draw the attention of the hon. Minister of Home Affairs to the appalling problems faced by the personnel of the Central Armed Police Forces.

Last month, we read the disturbing news of a Border Security Force (BSF) jawan who vented his grievance through social media. If we are to go by the media reports, the resentment over the allegedly poor quality food is just the outer layer of the problems, the discontent runs much deeper. The reports suggest that personnel in the CAPF are dissatisfied with the harsh service conditions.

They are expected to perform duties in snow-bound areas, in desert tracts and in jungle terrain, depending on the stations they are deployed at. They are over-stretched and on the move most of the time. There is also a high attrition level within the forces and large numbers go on voluntary retirement after completing the mandatory 20 years of service. The unplanned expansion of the Forces has led to visibly grave deficiencies in infrastructure. There is an acute shortage of housing in the Forces. About 95 per cent of the Forces remain deployed throughout the year and this affects the morale of the Forces. The men aren't even able to avail of their leave, which naturally leads to anger and resentment.

It is a matter of shame, Sir, that the brave jawans who protect our borders are unable to find ears within the system to voice their complaints. The existing grievance redressal mechanism seems weak and calls for a structured method to ensure that our jawans do not have

to employ social media to air their concerns.

At this juncture, Sir, some of the major recommendations of the six-member National Police Commission Report, submitted to Home Minister, Shri H.M. Patel, on February 7, 1979, seems valid even today and needs to be considered earnestly. The Commission had strongly recommended the establishment of District Police Staff Councils (DPSCs) and State Police Staff Councils (SPSCs) comprising a majority of subordinate policemen to consider the grievances of the personnel.

The Commission also recommended sanction of weekly off days and eight-hour workdays for all policemen. This step, I believe, will greatly help the jawans in recuperating from the stress that they undergo on a daily basis. Implementing a transparent, rational and fair leave policy will greatly reduce the burden on the personnel and refresh them for future commitments.

Another key issue concerns the salary paid to the personnel.

Although the CAPF personnel have been entrusted with duties akin to that of the Army, they draw lesser quantum of pay and allowances vis-

a-vis their Army counterparts and thus the fundamental principle.....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over.

SHRI PARTAP SINGH BAJWA: ...of equal pay for equal work is grossly violated in respect of CAPF personnel.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Bajwa*ji*, time is over. It is not going on record.

SHRI PARTAP SINGH BAJWA: Okay, Sir.

(Ends)

SHRI TAPAN KUMAR SEN (WEST BENGAL): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI MD. NADIMUL HAQUE (WEST BENGAL): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI RAM CHANDRA PRASAD SINGH (BIHAR): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI T.K. RANGARAJAN (TAMIL NADU): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

श्री राम नाथ टाकुर (बिहार): महोदय, मैं भी इस विषय के साथ स्वयं को सम्बद्ध करता हूं। श्री विवेक गुप्ता (पश्चिमी बंगाल): महोदय, मैं भी इस विषय के साथ स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Time over. Shuklaji, do you want to associate?

SHRI RAJEEV SHUKLA (MAHARASHTRA): Sir, it is a matter of serious concern. The jawans of Paramilitary Forces live in the most miserable and pathetic conditions and they are compelled to put it on social media. I think some preventive measures must be taken. On the one hand, there is an issue of discipline and on the other hand, nothing is being done to provide justice to them.

(Contd. by PB/1E)

PB-SC/1E/11.20

SHRI RAJEEV SHUKLA (CONTD.): They are compelled to do that. So, I think, the Government should come out with a statement, and the Home Minister should make a statement on the floor of the House. This is what I demand.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. All right. Now, Shri Derek O'Brien.

SECURING INTERESTS OF INDIAN I.T. WORKFORCE CREATING VALUE GLOBALLY.

SHRI DEREK O'BRIEN (WEST BENGAL): Sir, the subject today is, 'Securing the interests of Indian IT firms creating value globally'.

Sir, this is a very important subject, and a few days ago, the Chief Minister of West Bengal was the first person to react on this. I just want to read two lines of that quote before I get into the meat. 'News about H1B visas is concerning. We must protect our IT companies and professionals. They are our pride. They are our inspiration. We stand by them. India is proud of its world-class talent and it is our duty to secure their interests. We pledge our solidarity with our IT professionals across the world'.

Sir, I don't want to get into discussing what this new executive order does but, suffice to say that it will fundamentally and adversely affect Indian IT companies. Now Indian IT companies don't need our pity nor do they need our sympathy. They are very, very strong to stand on their own feet, and there is an alternative view, Sir, but I think it must be tabled as to what role these IT companies have played globally. Now, science and medicine doctors, technology, science professionals are always in short supply and it is well known that Indians across the world always come and top them up. No one is doing us a favour. It is because we are qualified to do what we

Sir, there are three or four very important points to highlight here. Seventy-five per cent of 'Fortune 500 companies' have operational support from Indian IT companies. I am not only talking about the 'Fortune 500 companies', I am also talking about the thousands of other American companies which have this support. Sir, from 2011 to 2015 when the American job market had been growing at 1.7 per cent, those Indian companies, supporting American companies, were growing at 10 per cent. That is a huge contribution. Sir, if it even comes to tax, 20 billion is being contributed every year by these companies. Sir, there are millions of jobs which are being created as a result. So, we need to protect these companies. We fully believe that these companies can stand on their own feet. I don't mean 'protection' in negative kind of way. There is an alternative view to suggest that these companies could be looking globally, elsewhere but I think we need to place on record that these companies play a positive role not only in the American economy but also across the world. Sir, these engineers, these software engineers, are truly a jewel in the crown of the Indian workforce, of the international workforce. Thank you, Sir.

(Ends)

SHRI MD. NADIMUL HAQUE (WEST BENGAL): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI K.T.S. TULSI (NOMINATED): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI T.K. RANGARAJAN (TAMIL NADU): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI VIVEK GUPTA (WEST BENGAL): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI K. SOMAPRASAD (KERALA): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

MS. DOLA SEN (WEST BENGAL): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

(समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. All those who associate are welcome. Now, Shri Hariprasad.

N.H.R.C. REPORT ON RAPE OF 16 TRIBAL WOMEN IN BASTAR

SHRI B.K. HARIPRASAD (KARNATAKA): Sir, I would like to draw the attention of this House about the slogan of the NDA Government 'Sabka Sath, Sabka Vikas'.

Sir, it has become a fashion in Chhattisgarh. Way back in 2012, Meena Khalkho, 14-year old girl, was raped and murdered by the Police force, and, later,

she was branded as a 'Naxalite'. The then Congress President, Mr. Nand Kumar Patel, was killed by the Naxalites. I demanded for a judicial inquiry to this episode, and later in 2015, the Judicial Commission had submitted its report to the Assembly saying that 'Meena Khalkho was not a naxalite'. It is nothing but a *. Later, in 2013, Sir, we have witnessed Jalaimari *kand* where 40 children, aged between 6-13 years, in a tribal ashram were molested by the people in the ashram. Fortunately, the District Commissioner, DC, had exposed this episode but no action has been taken. Sir, recently, the *Indian Express* had reported the NHRC report indicting the State Government and the Police of

^{*}Expunged as ordered by the Chair.

f raping of 16 tribal women in Bastar region, especially, in Bijapur region, in the whole of Bastar.

(Contd. by 1f/SKC)

SKC-GS/1F/11.25

SHRI B.K. HARIPRASAD (contd.): Sir, I would like to stress upon the fact that in the whole of Bastar, there is no governance except on the National Highways. Way back in 2015, according to the Commission Report, in Pegdapalli, Chinnagelur, Peddagelur, Gundam and Burgicheru, the State Police personnel allegedly sexually harassed and assaulted more than 40 of them and gang raped at least two in Bijapur district of Chhattisgarh. It was also reported that belongings of many villagers were destroyed, stolen or scattered by the forces passing through these villages.

Sir, they talk about "सबका साथ, सबका विकास". In Bastar, it is not vikas but vinash. No action has been taken against the people or the Police who were responsible for such acts. NHRC has taken suo motu cognizance of the NGO which was fighting for the cause of the tribals. Instead of filing cases against the Police under The SC and ST (Prevention of Atrocities) Act, they have filed cases against the lawyers who were giving free legal aid to these tribals. They have filed cases against the NGOs, they have filed cases against the journalists, but they are yet to file a case against

these police officers. Unfortunately, despite such barbaric and beastly acts by the Police officers there, the name of one of the top officers has been recommended for the Presidential Award.

Sir, at this juncture, we demand that action be taken against these officers. If the Government believes in "सबका साथ, सबका विकास" then, it should dismiss the Government in *

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Time over. ... (Interruptions)...

SHRI SHANTARAM NAIK (GOA): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI VIVEK GUPTA (WEST BENGAL): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

MS. DOLA SEN (WEST BENGAL): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

^{*} Not recorded

SHRI TAPAN KUMAR SEN (WEST BENGAL): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI K.K. RAGESH (KERALA): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI T.K. RANGARAJAN (TAMIL NADU): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI MAJEED MEMON (MAHARASHTRA): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRIMATI RAJANI PATIL (MAHARASHTRA): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार): महोदय, मैं भी इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार): महोदय, मैं भी इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। श्री परवेज़ हाशमी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): महोदय, मैं भी इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

SHRIMATI WANSUK SYIEM (MEGHALAYA): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Venkaiah Naidu, do you wish to respond to this?(Interruptions)... Now, listen. ...(Interruptions)...

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Sir, this is not the way to condemn the entire......(Interruptions)...

The Zero Hour is not meant to condemn a particular Force. Let me make this very clear from the Government side. ...(Interruptions)...

SHRI B.K. HARIPRASAD: Sir, no action has been taken against people who committed these atrocities. What else can be done? ...(Interruptions)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, it is the naxalites and the maoists who have taken the law into their hands. ...(Interruptions)... They are killing innocent people. They are killing *adivasis*. They have killed a number of people. ...(Interruptions)... The police personnel who get into the job for their livelihood are also being put to untold miseries and even being killed. ...(Interruptions)... If they have sympathies for the naxalites and maoists, let them say so openly. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please. ... (Interruptions)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: The Police and the CRPF are doing a fairly difficult job. ...(Interruptions)...

SHRI B.K. HARIPRASAD: No, Sir. ...(Interruptions)... They should take action against those people. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Listen to the Minister. ...(Interruptions)... Listen to the Minister. ...(Interruptions)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, the Police, the CRPF and others are doing a difficult job. They are also staking their lives for the protection of the people there. ...(Interruptions)...

SHRI B.K. HARIPRASAD: Sir, they are.....(Interruptions)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: People who sympathize with these people talk about the Human Rights Commission! ...(Interruptions)... Human rights are for human beings; human rights are not for people who kill others, who spread terror and who stop development. ...(Interruptions)... This has to be clearly noted, Sir. The Zero Hour is not meant to defame the Forces and make allegations against officers. They are not here. ...(Interruptions)... If they have some evidence, let them write to the Government and the Government would take suitable action. ...(Interruptions)... But such political allegations against the Forces should not be allowed, Sir. I hope the Chair would take notice of this and such things would not be allowed in future. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ... (Interruptions)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, please allow me. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will allow you; please sit down.
...(Interruptions)... I said, I will allow. Sit down; I will allow you. If Mr.

Hariprasad has condemned any Force in particular, then I would go through the records and expunge it. ...(Interruptions)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, he talked about 40 raids. What is the evidence for those 40 raids and for the allegation that those children in the *Ashram* were raped? They have given a statement that they were not raped. ...(Interruptions)...

SHRI B.K. HARIPRASAD: The NHRC has given a report. What more do you want? ...(Interruptions)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: They are using the Parliamentary forum to make such sweeping allegations. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will go through the records. ...(Interruptions)...

SHRI NARESH GUJRAL: Sir, they cannot demoralize the Forces. ... (Interruptions)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Such allegations about the Forces and State should not be allowed at all. Chhattisgarh is one of the best performing and forward-looking States in the country. ...(Interruptions)... Their Party leader, the former Chief Minister, left the Party and went away. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Hariprasad, the only point is, any blanket allegation or any vague allegation for that matter against any Force of the

Government will be expunged. ...(Interruptions)... Please sit down. ...(Interruptions)... Yes, Mr. Tapan Kumar Sen.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, the fact of the case is that some abnormality is prevailing in those extremism-affected areas. The Force is surely playing a role there. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not the Forces, but may be some individuals who are doing it. ...(Interruptions)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: At the same time, if you look at similar situations prevailing at various places, there are cases of over-action and atrocities against the common people by abusing their rights in the name of the abnormal situations prevailing there.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But you cannot blame the entire Force for that.

That is the point. May be some individual.....(Interruptions)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Definitely, Sir. The Force cannot be blamed, but who is to be blamed for that?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Just one minute.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, let me complete. It is the concerned administration that is to be blamed.

(CONTD. BY HK/1G)

SHRI TAPAN KUMAR SEN (CONTD.): Who is to be blame? ... (Interruptions)... Please let me complete. ... (Interruptions)... 'Who is to be blamed'? It is the concerned administration. ... (Interruptions)... 'Who is to be blamed"? It is the concerned administration which is supervising the utilization of the Force there. ... (Interruptions)... The concerned administration is to be blamed and they are to take the responsibility. Zero Hour is definitely a proper legitimate hour to raise these problems of common people. ... (Interruptions)...

श्री मेघराज जैन : ये जवाबदेह हैं। ... (व्यवधान)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The issue is not that. ... (Interruptions)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Nobody including the Minister can ever question raising an issue in the Zero Hour. ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The issue is not that. ... (Interruptions)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Nobody can even question raising the issue. ... (Interruptions)...

MR. **DEPUTY CHAIRMAN:** Mr. Tapan, the issue İS not that. ...(Interruptions)... For the fault committed ...(Interruptions)... Listen, let it clear. ...(Interruptions)... Let make it me me clear. ...(Interruptions)... For the mistakes or wrongs committed by a person or two persons of a particular Force, you cannot blame the entire Force.

...(Interruptions)... This is the issue. ...(Interruptions)... That is all. ...(Interruptions)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Nobody is doing that. ...(Interruptions)...

Please do not overreact. ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. ... (Interruptions)...

that too. ... (Interruptions)...

Shri Somaprasad. ... (Interruptions)...

श्री मेघराज जैन : सर, इन्होंने पैदा किया है। ..(व्यवधान)...ये जवाबदेह हैं। ..(व्यवधान)..

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN):

Don't we have to discuss Kerala, Sir, where our party workers are being murdered every day? Please discuss that too, Sir. ... (Interruptions)... Our party workers are murdered in Kerala. ... (Interruptions)... Please discuss

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri K. Somaprasad. ... (Interruptions)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: At the same time, the entire State administration has to be condemned. ...(Interruptions)... The entire administration has to be condemned. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is over. ... (Interruptions)... No discussion. ... (Interruptions)... I have not allowed any discussion. ... (Interruptions)...

What do you want? What is your problem? ... (Interruptions)... Why are you getting angry with me? ... (Interruptions)...

SHRI K.K. RAGESH: Sir, * is killing. ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. That is expunged. ... (Interruptions)...

श्री मेघराज जैन: लोगों की हत्या कर रहे हैं।..(व्यवधान)..

SHRI D. RAJA: This is a serious matter. ... (Interruptions)... We want some response. ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is already replied to. ...(Interruptions)...

Please sit down. ...(Interruptions)... That is already replied to.

...(Interruptions)... Don't be impatient....(Interruptions)...

SHRI K.K. RAGESH: Sir, * is killing. ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How do you say like that? ... (Interruptions)...

Why do you bring in the name of *? ... (Interruptions)... It is expunged.

... (Interruptions)... Don't do that. ... (Interruptions)...

^{*}Expunged as ordered by the Chair.

SHRI K.K. RAGESH: Sir, * is killing and they are pretending to be innocent. ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What are you doing? ... (Interruptions).. It is already expunged.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: He is telling what is actually happening there. ... (Interruptions)...

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. VENKAIAH NAIDU):

Let us discuss Kerala also. ...(Interruptions)... Let us discuss Kerala also. ...(Interruptions)...

SHRI K.K. RAGESH: It is not the CPI (M) but the ... (Interruptions)... The Minister is misleading the House. ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ragesh, if you have mentioned any organization, its name is expunged. ... (Interruptions)... Now, Mr. Ragesh, I am telling you that killing is going on from both sides. ... (Interruptions)... You cannot say that killing is from one side only. ... (Interruptions)... I also read newspapers. ... (Interruptions)... I don't want to apportion blame on

^{*}Expunged as ordered by the Chair.

anybody; but killing is from both sides. ...(Interruptions)... Now, Shri Somaprasad. ...(Interruptions)...

SHRI K.K. RAGESH: People were killed by *. ... (Interruptions)... They are doing that. ... (Interruptions)...

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: It is the Chair which decides. ... (Interruptions)...

SHRI K.K. RAGESH: * is doing that. ... (Interruptions)... It is the * which is doing it. ... (Interruptions)... (Ends)

PROBLEMS BEING FACED BY KERALA MINERALS AND METALS LIMITED

SHRI K. SOMAPRASAD (KERALA): Sir, with your permission, I raise certain points relating to Kerala Minerals and Metals Limited. The Kerala Minerals and Metals is a public limited company and Government of Kerala Undertaking. The peculiarity of the company is that it is the only manufacturer of rutile grade titanium dioxide in India. The company started its production in 1984 with the capacity of 40,000 metric tonnes per annum.

^{*}Expunged as ordered by the Chair.

The company produces five different types of titanium products. One of the products is titanium pigment. The titanium pigment plant is a joint venture of KMML with VSSC and DMRL. Titanium pigment is the raw material for the titanium metal. Titanium pigment is famous for its high strength and less weight.

*Expunged as ordered by the Chair.

Titanium metal is used in the manufacture of aeroplanes and it is also used in nuclear plants.

(Contd. by YSR/1H)

-HK/YSR-ASC/11.35/1H

SHRI K. SOMAPRASAD (CONTD.): Thus, the KMML becomes a strategically important company. It gives employment to 1,600 persons directly and more than 10,000 persons indirectly. Nowadays, the company is facing so many challenges.

China is one of the major producers of titanium dioxide. China has even penetrated the Indian market. They offer very cheap price which our Indian companies can never imagine. The KMML cannot compete with China even in our market. The import duty on titanium dioxide is only ten per cent. It should be enhanced to a minimum of twenty-five per cent. Only then the KMML can survive.

The Government of India should do something in this matter. My humble request is that the Government should enhance the import duty, which is now ten

per cent, to a minimum of twenty-five per cent. Thank you, Sir.

(Ends)

SHRI TAPAN KUMAR SEN (WEST BENGAL): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member. Hon. Commerce Minister is here. I request her to kindly respond to this serious issue. I know she has a mind of doing that.

SHRI T.K. RANGARAJAN (TAMIL NADU): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI C.P. NARAYANAN (KERALA): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI K.K. RAGESH (KERALA): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member. It is extremely important to increase the import duty on titanium dioxide from ten per cent to twenty-five per cent. In the last two decades, many public sector units had closed down because of liberalisation policy and that is why it is extremely important to increase the import duty on titanium dioxide to save the KMML.

(Ends)

RELEASE OF FATHER TOM UZHUNNALIL FROM CAPTIVITY IN YEMEN

SHRI JOY ABRAHAM (KERALA): Mr. Deputy Chairman, I thank you for giving me this opportunity.

Sir, I wish to raise the issue of Father Tom Uzhunnalil, an Indian citizen and native of Kerala, who was serving in Yemen. He has been in the captivity of terrorists in Yemen for the last several months. All efforts by the Government to get his release are in vain. It seems that his life is in danger. Recently, a video clipping, in the form of appeal by Father Tom, appeared in the visual media. His appeal was so passionate that it moved the hearts of everybody who viewed it. It seems that his health is deteriorating day by day. A dharna under the auspices of Archdiocese of Faridabad and All Kerala Catholic Congress is being staged today at Jantar Mantar to draw the attention of the Central Government for its speedy intervention. request that someone from the Government's side respond to this humanitarian issue. I seek the help of the whole House to get the release of Father Tom as early as possible.

(Ends)

SHRI K. SOMAPRASAD (KERALA): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI C.P. NARAYANAN (KERALA): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI K.K. RAGESH (KERALA): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI D. RAJA (TAMIL NADU): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not a Catholic issue. It is an issue concerning all of us. I think hon. External Affairs Minister has already made a statement.

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I am sure the House is aware that the External Affairs Minister, Shrimati Sushmaji, had spoken about it and efforts were being made on this issue. Because he is an Indian citizen, we all have to be concerned about this. I am sure the External Affairs Ministry will be able to give extra information on the latest position. I have got up only to remind that the House was earlier given information how the External Affairs Ministry was definitely taking the matter up. I am sure the Parliamentary Affairs Minister, Mr. Naqvi, will be

able to pass on the message. I just want to remind the House that the efforts were on at that time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I saw that statement. Naqviji may kindly convey the feelings to the External Affairs Minister and, if possible, share the position with the House.

(Ends)

DEMAND FOR C.B.I. INQUIRY INTO CASE OF MISSING STUDENT OF J.N.U.

श्री विवेक गुप्ता (पश्चिमी बंगाल): डिप्टी चेयरमैन साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने आज मुझे यहां खड़े होकर बोलने का मौका दिया। सर, एक छात्र नज़ीब है, जो कई महीनों से लापता है। आज मेरे ज़ीरो ऑवर का सब्जेक्ट उसी के बारे में है। सर, नज़ीब का मतलब होता है, जो सराहनीय है।

(1J/LP पर जारी)

LP-VKK/11.40/1J

श्री विवेक गुप्ता (क्रमागत): मगर जे.एन.यू. के जो अधिकारी हैं, उनका जो आचरण है, उनका जो तौर-तरीका है, वह सराहनीय नहीं है। वॉर्डन की रिपोर्ट के मुताबिक 14 अक्तूबर, 2016 को यह घटना घटी, जिसमें नज़ीब और कुछ और छात्र शामिल थे। वे छात्र किसी राजनीतिक दल से संबंध रखते थे। मैं दल का नाम नहीं लेना चाहता हूं,

उस पर नहीं जाना चाहता हूं। वहाँ पर एक झमेला हुआ। सिक्युरिटी गार्ड, स्टुडेंट्स और वॉर्डन इंचार्ज, इन सभी ने इस घटना को देखा। इसकी रिपोर्ट बनाकर दी गई, मगर आश्चर्य की बात यह है कि वाइस चाँसलर से लेकर जितने भी अधिकारी इस युनिवर्सिटी के हैं, उनमें से किसी के द्वारा भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ तक कि एफ.आई.आर. दर्ज़ कराने के लिए भी लड़के की माँ को जाना पड़ा। इसके पहले कि सरकार यह बोले कि यह युनिवर्सिटी का आंतरिक मामला है और हम लोग उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, मुझे लगता है कि शायद लॉ एंड ऑर्डर सरकार का मामला है, और दिल्ली राज्य का होने से खास कर केंद्र सरकार का मामला है। क्या हम लोग नज़ीब को सिर्फ एक गुमशुदा स्टेटेस्टिक्स बनने देंगे? मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से जानना चाहूंगा कि नज़ीब को खोजने के लिए क्या कुछ स्पेशल प्रयास किए गए हैं? क्या नज़ीब सिर्फ एक missing student की तरह बनकर रह जाएगा, जबिक यह एक क्लियर कट पोलिटिकल वेंडेटा का केस है?

सर, आजकल हम लोग देखते आ रहे हैं कि देश में पोलिटिकल वेंडेटा किस तरह से कैंसर की तरह फैलता जा रहा है। अगर कोई सरकार में है, तो उनका यह प्रयास होना चाहिए कि नज़ीब को जल्द से जल्द खोजा जाए। उसके घरवालों से, उसकी माँ से ज्यादा से ज्यादा बातचीत की जाए, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वाइस चाँसलर ने उनकी माँ से मिलने तक के लिए मना कर दिया था। सर, अगर उन लोगों में संवेदना नहीं है तो कम से कम केंद्र सरकार वह संवेदना तो जगा सकती है। मेरी आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि सरकार इस पर या तो सीबीआई इंक्वायरी कराए या कोई अन्य उचित इंक्वायरी करवाए। सरकार यह पता तो लगवाए कि यह जो नज़ीब गया है, उसके पीछे क्या कारण थे, जबिक हम लोगों को घटनाएँ मालूम हैं? सर, मजे की बात यह है कि जो लोग, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र, इस घटना में इन्वॉल्व हैं उनसे आज तक पूछताछ तक नहीं हुई है। सर, यदि उन लोगों का कुछ स्पेशल स्टेटस है, तो हम लोगों को यह भी बता दिया जाए कि उनको पूछताछ से क्यों एग्जम्प्ट किया हुआ है?

सर, देश में यह जो पोलिटिकल वेंडेटा हो रहा है, यह एक बड़ा इश्यू बनता जा रहा है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार के संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाए और उचित कार्यवाही की जाए। हम लोगों को कम से कम एक उचित स्टेटमेंट दी जाए कि पोलिटिकल वेंडेटा पर सरकार का क्या रुख है? धन्यवाद।

(समाप्त)

श्री अली अनवर अंसारी: उसको जमीन निगल गई या आसमान उठा ले गया? कहाँ चला गया लड़का? ..(व्यवधान).. अभी तक जाँच नहीं कर रही है। ..(व्यवधान)..एक खास दल से संबंधित लड़कों..(व्यवधान)..को नहीं देख रही है, पुलिस उनसे पूछताछ नहीं कर रही है। यह क्या हो रहा है? ..(व्यवधान)..एक तरफ तो रोहित वेमुला को स्युसाइड करने के लिए मजबूर किया जाता है और दूसरी तरफ नज़ीब को मार दिया जाता है..(व्यवधान) और यह जाँच तक नहीं करेगी। ..(व्यवधान)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. You associate. That's okay. ...(Interruptions)... What do you want to say? ...(Interruptions)...

SHRI MAJEED MEMON: Sir, the offence against the State needs to be examined, investigated and the law must take its own course. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. You associate. ... (Interruptions)...

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करती हूं।

श्री जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

جناب جاوید علی خان (اترپردیش): اُپ سبهاپتی جی، میں بھی خود کو اس وشے سے سمبد کرتا ہوں۔

SHRI MD. NADIMUL HAQUE (WEST BENGAL): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Vivek Gupta.

SHRI MAJEED MEMON (MAHARASHTRA): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Vivek Gupta.

SHRI HARIVANSH (BIHAR): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Vivek Gupta.

MS. DOLA SEN (WEST BENGAL): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Vivek Gupta.

SHRI AHAMED HASSAN (WEST BENGAL): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Vivek Gupta.

SHRI T.K. RANGARAJAN (TAMIL NADU): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Vivek Gupta.

SHRI K.T.S. TULSI (NOMINATED): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Vivek Gupta.

SHRI TAPAN KUMAR SEN (WEST BENGAL): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Vivek Gupta.

SHRI C.P. NARAYANAN (KERALA): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Vivek Gupta.

SOME HON. MEMBERS: Sir, we also associate ourselves with the matter raised by Shri Vivek Gupta.

(Ends)

CONCERN OVER POOR CONDITION OF EX-SPORTSPERSONS OF COUNTRY

SHRI MD. NADIMUL HAQUE (WEST BENGAL): Sir, I thank you for giving me this opportunity. Sir, I want to speak about the tragedy of those who made our nation proud, that is, our ex-sportspersons.

जब अपनों ने दिया दर्द, तो दुनिया से क्या कहना यूँ तो लाखों दर्द मिले हैं हमें, पर इस दर्द का क्या कहना। جب اپنوں نے دیا درد، تو دنیا سے کیا کہنا یوں تو لاکھوں درد ملے ہیں ہمیں، پر اس درد کا کیا کہنا Sir, while the nation is celebrating our recent win in cricket against England, there is a sad state of affairs which I would like to bring to the notice of the House through you.

A nation must honour its heroes — be it a soldier, a sailor or a sports star. Wherever they go, they are the ones who carry our country's pride and cause with them. But, are we doing enough to honour those who make our nation proud? Are we taking care of those athletes who won medals for us? Though the Ministry of Sports has always talked about the efforts to improve sports facilities in the country, it is important that they also start talking about the efforts to honour ex-sportspersons who brought glory to our nation. Sir, I am deeply saddened by the way they have been pushed to the margins of sports history and by the fact that they have to spend their lives in poverty, struggling to make ends meet.

(Contd. by GSP/1K)

GSP-KLG-11.45-1K

SHRI MD. NADIMUL HAQUE (CONTD.): Sarwan Singh, a gold medalist in 110m hurdles at the 1954 Asian Games worked as a cab driver and finally as an agricultural labourer at the age of 70 years.

Yousuf Khan was part of the gold medal winning team in soccer in the 1962 Asian Games. In the same Games, Makhan Singh won the relay race. Both led poverty stricken life after retirement. Gopal Bhengra, a 1978 world cup participant had to work in a stone quarry. Kabaddi champion Shanti Devi sells vegetables whereas Sita Sahu who won two bronze medals at the 2011 Special Olympics in Athens now sells *gol gappas*. I have named a few though there are numerous such cases. A small amount of monthly pension is now granted to our retired sportspersons from the Sports Fund for Pension to Meritorious students but we need to ask ourselves, is it enough?

बेटा कैसा भी हो जाए, पर मां तो मां ही होती है। तू झांक के दिल में देख कभी, हम कितने दर्द समेटे हैं। मां हम भी तेरे बेटे हैं, मां हम भी तेरे बेटे हैं।

Sir, I would like to bring to the notice of the House the poor financial conditions of some of our ex-sportspersons. It is their voice that I raise here, when I say.

भीगी पलकों से एक बेटा भारत मां से कहता है।

मां हम भी तेरे बेटे हैं, मां हम भी तेरे बेटे हैं।

بهیگی پلکوں سے ایک بیٹا بھارت ماں سے کہتا ہے

ماں ہم بھی تیرے بیٹے ہیں، ماں ہم بھی تیرے بیٹے ہیں۔ समाप्त)

श्री विवेक गुप्ता (पश्चिमी बंगाल): महोदय, मैं इस विषय से अपने आपको संबद्ध करता हूँ।

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आपको संबद्ध करती हूँ।

श्री राम नाथ टाकुर (बिहार): महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आपको संबद्ध करता हूँ।

श्री प्रफुल्ल पटेल (महाराष्ट्र): महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आपको संबद्ध करता हूँ।

SHRI K.T.S. TULSI (NOMINATED): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRIMATI M. C. MARY KOM (NOMINATED): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI A.V. SWAMY (ODISHA): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI B.K. HARIPRASAD (KARNATAKA): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. T. SUBBARAMI REDDY (ANDHRA PRADESH): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI D. RAJA (TAMIL NADU): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI PARVEZ HASHMI (NCT OF DELHI): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI ALI ANWAR ANSARI (BIHAR): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is full support. Naqvi ji, you also heard what Mr. Haque has said. Many of our ex-sportspersons are starving and finding it very difficult to make both ends meet. That is what he said. He is suggesting something. Why don't you convey it?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY

AFFAIRS (SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI): Right, Sir. ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think, it is a very reasonable demand.

... (Interruptions)...

श्री प्रेम चन्द गुप्ता: उपसभापति जी, यह एक इंपॉर्टेंट इश्यू है। Across the party lines, it is the same feeling.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Everybody is supporting it.

श्री प्रेम चन्द गुप्ताः कोई किसी एक पार्टी का इश्यू नहीं है। What I suggest is that we should have a one hour discussion on this issue, which is very important.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, somebody can give notice.
...(Interruptions)... I think, in this Session... ...(Interruptions)... It may not be possible before......(Interruptions)...

SHRI PREM CHAND GUPTA: Next session, Sir. ...(Interruptions)... It is a very important issue.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, I also agree with you. Notice can be given and the hon. Chairman may consider it. I will also request hon. Chairman to consider it. I agree with you.

Now, Shrimati Kahkashan Perween, not present. Okay. Now, Special Mentions. (Ends)

SPECIAL MENTIONS

URGENT NEED TO ADDRESS GENDER INEQUALITY

SHRI K.C. RAMAMURTHY (KARNATAKA): Sir, I thank you for giving me the opportunity. Sir, this issue has been discussed many times here. However, I would like to mention the urgent need to address gender inequality. Sir, gender inequality in India is a growing concern. As per UN Gender Inequality Index, India ranks abysmally 127 out of 146 countries in gender inequality. Even McKinsey's Report "The Power of Parity: Advancing Women's Equality in India shows poor levels of gender parity.

And, our global Gender Parity Score is 0.48 whereas a score of 1 would be ideal. It represents 'extremely high' level of gender inequality, which compares poorly with 0.71 for Western Europe, 0.74 for North America and Oceania.

No doubt a significant progress on promoting girls' education and advancing gender equality is made, but stark inequalities still exist between men and women in their access to education, healthcare, resources and opportunities in socio- economic and cultural spheres. Just 13 per cent of women of low economic status avail institutional deliveries, while only 19 per cent in the lowest quintile avail any kind of post-natal care. Adverse child (0-6 years) sex ratio of 914 in 2011 when compared to 927 in 2001 gives grim reminder of continuing aversion to girl child and tempering natural demography. Female literacy rate is 65 per cent against 81 per cent for men and 97 per cent women undergo sterilisation.

So, it is imperative to address low status of women as a national priority by channelizing potential of our 300 million young people to catapult itself into a new trajectory of development. Programmes that educate adolescents and young males and females to influence their health and consequently their overall well-being are an absolute priority, apart from

investing in skill development on young.

(Ends)

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (TAMIL NADU): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRIMATI RAJANI PATIL (MAHARASHTRA): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

(Ends)

-GSP/BHS-AKG/1L/11.50

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, just on the issue of business in the House today and tomorrow, all we have is the President's.....(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...(Interruptions)...

SHRI DEREK O'BRIEN: One second, Sir. It is just to clarify. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: After this, I will. I think, we will finish this. Then, I will allow you. There will be time. Now, Shri Vivek Gupta.

DEMAND FOR TAKING STEPS TO MAINTAIN SPIRIT OF COOPERATIVE FEDERALISM IN THE COUNTRY

श्री विवेक गुप्ता (पश्चिमी बंगाल): सर, आपका एक बार फिर धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। Special Mention पढ़ने का मौका बहुत कम मिलता है।

सर, हमारे प्रधान मंत्री जी ने अभी थोड़े दिन पहले ही कहा था कि भारत की ताकत उसका federal character और federal structure है और हम स्टेट्स के साथ बड़े भाई के attitude में विश्वास नहीं रखते हैं। "We believe in cooperative federalism." उनके स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि सरकार को स्टेट्स की मदद करनी चाहिए। सरकार को एक स्टेट को उसके कामकाज करने देने में पूरी-पूरी मदद करनी चाहिए और उसको इसके लिए जिस-जिस चीज की दरकार है, वह देनी चाहिए। सर, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में कुछ आँकड़े लाना चाहता हूँ। पश्चिमी बंगाल सरकार को 2011 में करीब ढाई लाख करोड़ का कर्ज मिला था। 5 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन केन्द्र सरकार ने न तो हमें कोई फंड दिया है, न हमारी कोई मदद की है, न कोई moratorium किया है, कुछ भी नहीं किया है। मगर, surprisingly, हम लोग विदेशी देशों की जा-जाकर मदद कर रहे हैं। सर, पश्चिमी बंगाल में 101 IAS ऑफिसर्स की shortage है और 88 IPS ऑफिसर्स की shortage है। इस demand को सरकार के साथ regularly उठाया जा रहा है, मगर अभी तक हमारे पास सरकार से कोई response नहीं आया है।

इसके अलावा, आजकल देखा गया है और last six months में हमारी दीदी, hon. Chief Minister of West Bengal ने कई बार इस issue को उठाया है कि आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे फैसले बिना स्टेट गवर्नमेंट को consult किए arbitrarily लेती है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...(Interruptions)... Vivek*ji*, you have to read from the prescribed page. ...(Interruptions)...

SHRI VIVEK GUPTA: Yes, Sir. I am reading. I am just reading in Hindi. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You cannot go out of that. ...(Interruptions)...

SHRI VIVEK GUPTA: I am not going out of it. ...(Interruptions)... I am just reading in Hindi. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please read that. ...(Interruptions)...

SHRI VIVEK GUPTA: I have given in English but I am reading in Hindi.

श्री उपसभापति : ठीक है, आप पढ़िए।

SHRI VIVEK GUPTA: It is a literal Hindi translation, Sir. You can check it. I will go as per your instruction, Sir.

The Central Government has now taken a decision (without consulting the States) to remit money under MNREGA directly to the beneficiaries against the earlier practice of involving States in the process of remitting the same.

Despite regular audits done by the CAG, the Central Government recently appointed two senior officers to monitor the working and spending of the Treasury of the Bengal Government. Sir, we feel this is a direct attack on our fiscal independence.

Despite all these challenges, the hon. Chief Minister of West Bengal has made Bengal grow by leaps and bounds. We hope the Government takes these concerns seriously and lays more trust with the State Governments by decentralizing greater powers. Thank you, Sir.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much. Now, Dr. V. Maitreyan, not present. Shri T. Rathinavel, not present.

Now, hon. Members, I will allow Derek O'Brienji. You are going to speak on the listed Business of the House, isn't it? I am going to allow you. Now, I am also going to say about the Business of the House. See, how productive and fruitful was this one hour! All could raise their issues. The Government could react in some cases. Even Special Mentions could be read. So, now, compare it with the days of disruption. That is all what I have to say. ...(Interruptions)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, I read your interview today. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; that is all. So, let us do like this. It will be good for all of us. ...(Interruptions)...

SHRI DEREK O'BRIEN: You look at this side also. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, both sides. ...(Interruptions)... I am talking to both sides. ...(Interruptions)... No doubt about it. ...(Interruptions)... Both sides should cooperate. Now, Shri Derek O'Brien. SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, just on one point on the List of Business as we understand, so that we do not get into a situation, when we are discussing the Budget, as happened about four-five years ago. Due to paucity of time, all the 35 speakers who wanted to speak on the Budget were asked to lay their speeches on the Table.

(Contd. by DC/1M)

DC-RPM/1M/11.55

SHRI DEREK O'BRIEN (CONTD.): Sir, if this finishes today or tomorrow, as we are going, then, the next two days after that are on the Budget. Everybody gets a chance to speak then. So laying is not a solution. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Laying is not a...(Interruptions)...

SHRI DEREK O'BRIEN: There is a precedent of three or four years ago when Chidambaram*ji* was the Finance Minister. There was no fault of Chidambaram*ji*, but we were in the House and about 22 speakers laid their Budget speeches. I said, 'let us...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That must be a special permission perhaps given by the hon. Chairman.

SHRI DEREK O'BRIEN: Protect us, Sir. Protect us as you complimented the Government and the Opposition for running the House together. So protect us. On Wednesday and Thursday, we all can make our Budget speeches and no speech needs to be laid. That is my only contention.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes; there is no rule to allow it to be laid on the Table but, however, I have to question one thing.....(Interruptions)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, the House is working in a very serious manner and the issues have been taken up and discussed. I seek your indulgence for a minute. A very serious situation has arisen in recent days because of the various laws that have been proposed or tabled in the US Congress.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Let us conclude this issue first.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, if you conclude that...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, I did not conclude that. I thought you are on this issue. Regarding the List of Business, I have to ask the House. For this Motion of Thanks on the Presidential Address, 12 hours is the time allotted. We have exhausted only four hours. So another eight hours are there, and we have today and tomorrow. It will be over only by tomorrow. I think the

reply should be by tomorrow evening. What is the position? Can you tell us, Mr. Minister?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक़वी): माननीय उपसभापित जी, जो डिसकशन है, वह आज होगा और कल होगा। रिप्लाई के बारे में, डिसकशन के बाद क्या स्थिति है, उसे देखने के बाद बताएंगे। Then I will convey it to you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; that is all right. Then, for Budget, there are only two days.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, it has 16 hours.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Budget has 16 hours. Then how is it possible? That is the point. How is it possible in two days? What is the way out? ...(Interruptions)... Mr. Derek, you please listen. According to the Business listed on Thursday, there is the Private Members' Business also. First thing is, we will have to postpone the Private Members' Business. The House has to do that. That is number one. Number two, even then it is not possible to have 16 hours. ...(Interruptions)... So, in practice, it may not be possible to conclude the Budget in two days. ...(Interruptions)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: So the Budget discussion has to spill over to the Session, starting from 9th March.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is all what I want to say.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, my suggestion is, whatever Budget discussion remains, it should spill over to the Session, which is starting from 9th March and going up to 12th April, because we are very much within the penultimate date and as per the Constitutional mandate, we can have the discussion and then pass it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Otherwise, there is a way out. Today and tomorrow also, let us sit late. If that is not possible, the Budget discussion cannot be completed by Wednesday and Thursday.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Why should you make us sit late? We are very much within the time. ...(Interruptions)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, ...(Interruptions)... Just one minute. ...(Interruptions)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: And the hon. Parliamentary Affairs Minister cannot say like that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Anand Sharma, you have only two minutes.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, I just have to make this submission that I agree with our colleagues here. The Budget has to be passed before the 31st March. Now, 16 hours have been allocated for the Budget discussion. That may not be possible. The Budget has been presented by the Government. Heavens will not fall. Why should we be pushed? This should spill over. The

allotted 16 hours have to be completed because this is an important Budget and this is the first time, Sir, that the General Budget and the Railway Budget have been combined. This is the first time; otherwise, there used to be separate time for General Budget and separate time for Rail Budget. Sir, it would only be fair that the discussion starts and continues. Here nothing is going to happen.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; we will try. We can try. We all will try. SHRI ANAND SHARMA: Sir, we still have a minute. The issue which I was raising is about the H-1B Visas. The Bills have been tabled in the US Congress. Over three lakh Indian professionals are there, their careers are threatened. They are afraid to come to India even for family emergencies because they may not be allowed to return. Sir, the Government must make a statement. If we are investing in strategic partnerships with the United States of America, then the US administration and the new President have to be fully sensitized and credible assurances must be sought by our Prime Minister, Shri Narendra Modi, from President Trump.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is time for Question Hour.

(Ends)

(12.00-1.00 P.M. - Question Hour)